तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

1415. **श्रीमती रत्न कुमारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के सहयोग से तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित कर कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने राज्य सरकारों या केन्द्रीय अधिकरणों के माध्यम से किसानों को अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिक संख्या में किसानों में बीजों का वितरण करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित "तिलहन उत्पादन कार्यक्रम" के अंतर्गत रियायती दरों पर बीज मिनीकिटों के वितरण तथा प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की सप्लाई का एक कार्यक्रम शुरु किया गया है । केन्द्रीय स्तर पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम तथा राज्य स्तर पर बीज निगमों, कृषि विभागों एवं कृषि विश्वविद्यालयों जैसी विभिन्न एजेंसियों के जरिये बीजों की सप्लाई तथा वितरण की व्यवस्था की जाती है ।

Decline in growth rate of agricultural Production

1416. SHRI SOM PAL:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that growth rate in agricultural production has declined during the Seventh Plan Period;

(b) if so, what are the factors responsible for this decline ; and

(c) what steps Government are taking to ensure that agricultural growth is accelerated during the Eighth Plan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN) : (a) No, Sir. The growth rate of production of all crops, based on point to point basis, was higher in Seventh Five Year Plan than that of Sixth Five Year Plan.

(b) Does not arise.

(c) To accelerate the agricultural growth during Eighth Plan, the Government has taken number of steps such as:

(i) More thrust to areas of the Eastern and North Eastern Region where the Green Revolution has not reached so far.

(ii) To bring more areas under assured irrigation and high yielding varieties.

(iii) Continuation of on-going production programmes with more thrust on low yielding areas.

(iv) To transfer newly developed crop production technologies through demonstration and training.

(v) To provide resourceless cultivators, subsidized inputs such as seeds, fertilizers, pesticid etc.

(vi) To diversity and accelerate agro-based rural activities.

भानु प्रताप सिंह समिति की सिफारिशें

1417. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री सत्यप्रकाश मालवीय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "कृषि नीति और कार्यक्रमों संबंधी भानु प्रताप सिंह समिति" द्वारा की गयी सिफारिशों पर कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) भानु प्रताप सिंह समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है तथा समिति को विभिन्न सिफारिशों से संबंधित सूचना कुछ मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की जानी है ।

"राष्ट्रीय कृषि नीति" के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विचार

1418. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :
कुमारी आलिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों और कृषि विश्वविद्यालयों ने "राष्ट्रीय कृषि नीति" के प्रारूप के संबंध में अपनी टिप्पणियां केन्द्रीय सरकार को भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस नीति को कब तक लागू किये जाने की संभावना और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय कृषि नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे क्रियान्वित करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

Fertiliser Subsidy

1419. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI RAM AWADHESH SINGH:
SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what was the value of fertilizer subsidy given during 1991-92 and that targeted for 1992-93;

(b) what has been the impact of cut in the subsidy in the cost of agricultural products like wheat and rice per acre due; and

(c) whether it is a fact that a large section of farmers has demanded withdrawal of subsidy altogether, if so, the reasons therefore.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) The budget provision for fertiliser subsidy during 1991-92 is Rs. 4800 crores and for 1992-93 it is Rs. 5000 crores.

(b) A statement indicating revised cost of cultivation of wheat and paddy per acre after taking into account the 30% increase in fertiliser prices is enclosed (*See* below)

(c) No, Sir.